

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 14 मई, 2010

विषय:-सरकारी कार्यालय के लिए निजी भवन किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-ए-2-996/दस-86-14(30)/73 दिनांक 30 सितम्बर, 1986 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभागीय अधिकारी अधिकतर बिना विज्ञापन किये निजी सम्पर्क से या अपने ही भवन किराये पर ले लेते हैं जिससे उपलब्ध अन्य भवनों को देखने का अवसर नहीं रहता है और इस प्रकार अपने भवनों को किराये पर देने के इच्छुक अन्य भवन स्वामी भी अपना आवेदन देने से वंचित रह जाते हैं। अतः सरकारी कार्यालयों हेतु निजी भवन किराये पर लेने के लिये निम्न प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाय:-

1-कार्यालय हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित मानक पर स्थान (Accommodation) की आवश्यकता का आकलन पहले कर लिया जाय।

2-सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कास्ट इफेक्टिव (Cost effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केन्द्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती हैं वहां पर भवन किराये पर लिये जाने से बचा जाय। उक्त स्थानों पर सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर तभी लिये जाए जब इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य हो।


3-ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि के बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक

समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराया जाय।

4-विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी। कमेटी द्वारा चयनित भवन के लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया औचित्यता के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

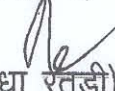

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या-539 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- एन0आई0सी, एकक सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राधा रस्तूड़ी)
सचिव।